



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2018/माघ 3, 1939

No. 36]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2018/MAGHA 3, 1939

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सं. आरएस. 46/2017-टी.— भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अधीन राज्य सभा के अन्य सदस्य, श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह के संबंध में राज्य सभा सदस्य (अब निरर्हित), श्री अली अनवर अंसारी की याचिका के मामले में राज्य सभा के सभापति द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2018 को दिए गए निम्नलिखित निर्णय को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:-

"आदेश

राज्य सभा में जनता दल (यूनाइटेड) [जद (यू)] दल के सदस्य (अब निरर्हित), श्री अली अनवर अंसारी (जिन्हें इसके पश्चात् यहां 'याची' कहा गया है) ने 30 अक्तूबर, 2017 को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के साथ पठित अनुच्छेद 102(2) और राज्य सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हिता) नियम, 1985 (जिन्हें इसके पश्चात् यहां 'नियमों' कहा गया है) के नियम 6 के अधीन मेरे समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि राज्य सभा के एक अन्य सदस्य और राज्य सभा में जद (यू) के नेता, श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह (जिन्हें इसके पश्चात् यहां 'प्रतिवादी' कहा गया है) को संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हित किया जाए और राज्य सभा में उनकी सीट रिक्त घोषित की जाए।

2. याची का मुख्य आरोप यह है कि प्रतिवादी ने श्री नीतीश कुमार के प्रति खुलेआम समर्थन और निष्ठा का वचन देकर और श्री नीतीश कुमार की कथित गलत गतिविधियों, जैसे (i) पार्टी संविधान के अनुसार जद (यू) के भीतर समय पर संगठनात्मक चुनाव का आयोजन नहीं करने; (ii) जद (यू) की राष्ट्रीय परिषद की ताकत को धोखाधड़ी के तरीके से कम करने के

लिए एक चतुर षड्यंत्र रचने ताकि उनके विरोध की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके; और (iii) *महागठबंधन* से अलग होने और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के समर्थन से बिहार में सरकार बनाने, जो सभी पूर्णतः राजनीतिक और अवसरवादी कारणों के लिए थे, में सहयोग करके और सक्रिय रूप से भाग लेकर बिहार के लोगों द्वारा अपने जनादेश के माध्यम से व्यक्त किए गए विश्वास को भंग कर दिया है और यह संकेत दिया था कि उनकी पार्टी और उसके संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा नहीं है। याची ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी के इन कार्यों और आचरण के परिणामस्वरूप उन्होंने स्वतः पार्टी और उसके संविधान का स्वैच्छिक परित्याग कर दिया है और इसके आवश्यक निहितार्थ के कारण उनकी पार्टी की सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी, जो कि जद (यू) टिकट पर राज्य सभा के लिए चुने गए थे, को राज्य सभा में जद (यू) विधानमंडल दल के नेता के पद से श्री शरद यादव को मनमाने, सनकी और स्वेच्छाचारी तरीके से हटाकर उक्त पद पर अवैध रूप से नियुक्त किया गया था, जो कि पार्टी के सिद्धांतों और उसके संविधान का पूर्ण उल्लंघन है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 19 अगस्त, 2017 को अवैध रूप से गठित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने और *महागठबंधन*, जिसे तत्कालीन विधिवत रूप से गठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा 20 और 21 दिसंबर, 2015 तथा राष्ट्रीय परिषद द्वारा 23 अप्रैल, 2016 को अनुमोदित किया गया था, से निकलने में श्री नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए यह संकेत दिया था कि उन्होंने जद (यू) के सर्वोच्च निकाय के बुनियादी नियमों, सिद्धांतों और बाध्यकारी प्रस्तावों से अलग रहने का फैसला किया था और वह राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी संविधान के प्रति कोई विश्वास या निष्ठा नहीं रखते हैं।

3. याची ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने पूर्णतया व्यक्तिगत लाभ और राजनीतिक अवसरवाद के लिए श्री नीतीश कुमार और उनके गुट के साथ सहयोग किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के गुट की निरंकुश और गैर-लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली ने नीतीश कुमार गुट को अधिकांश कार्यकर्ताओं और जद (यू) के संगठनात्मक निकायों के सदस्यों से अलग कर दिया है और उन्हें अल्पसंख्यक छोटा समूह बना दिया है, जिसने वास्तविक जद (यू) राजनीतिक दल के साथ संबंध तोड़ लिया है। याची ने आगे कहा कि केवल यह तथ्य कि राज्य और संसद, दोनों में जद (यू) विधान मंडल दल के अधिकांश सदस्यों ने समान रूप से व्यवहार किया है, उनके अवैध कार्यों को वैध ठहराने और स्वैच्छिक रूप से निरर्थक हो जाने से बचाने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में, याची ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) में पहले से लंबित विवाद की ओर ध्यान आकर्षित कराया, जिसमें उन्होंने श्री शरद यादव और अपने समर्थकों के साथ उनके गुट को वास्तविक जद (यू) के रूप में मान्यता देने और पार्टी के चुनाव चिन्ह, तीर, उन्हें आवंटित करने की मांग की थी। अपने आरोपों के समर्थन में, याची ने समाचारपत्रों के अंशों, जद (यू) के संविधान; महागठबंधन के कार्यक्रम और नीतियों; 20 से 21 दिसंबर, 2015 तक आयोजित जद (यू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित संकल्प; 23 अप्रैल, 2016 को आयोजित बैठक में राष्ट्रीय परिषद द्वारा पारित संकल्प; वर्ष 2016 में जद (यू) के भीतर संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम; 17 सितंबर, 2017 को हुई बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पारित संकल्प; 8 अक्तूबर, 2017 को आयोजित बैठक में राष्ट्रीय परिषद द्वारा पारित संकल्प; ईसीआई के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न अभ्यावेदनों/याचिकाओं और इस संबंध में ईसीआई द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ 17 अक्तूबर, 2017 के अंतिम आवेदन और प्रतिवादी द्वारा नीतीश कुमार गुट के समर्थन में ईसीआई के समक्ष दिनांक 22 अगस्त, 2017 को दायर शपथ पत्र की प्रतियां संलग्न की हैं।

4. इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि याचिका नियमों के नियम 6 की शर्तों का अनुपालन करती है, मैंने 10 नवंबर, 2017 को नियम 7 के उप-नियम (3) के संबंध में उक्त याचिका और उसके साथ संलग्न सभी अनुलग्नकों की एक प्रति इस अनुरोध के साथ प्रतिवादी को अग्रेषित करने का आदेश दिया कि प्रतिवादी इसकी प्राप्ति के सात (7) दिनों के भीतर लिखित रूप में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

5. प्रतिवादी ने 13 नवंबर, 2017 को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि याचिका गलत है और विचार करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह न केवल गलत तथ्यों, जिनका कोई आधार नहीं है, पर आधारित है अपितु नैतिकता और नैतिक मूल्यों के मानकों पर एक व्याख्यान भी है, जो न तो प्रासंगिक हैं और न ही दसवीं अनुसूची के अधीन जांच करने योग्य है। प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किया है और स्पष्ट रूप जोर देकर यह कहते हुए उन्हें झूठा और तथ्यों की दृष्टि से गलत बताया है कि जद (यू) के नेतृत्व के बारे में कोई विवाद नहीं है और जद (यू) के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जो पार्टी के एकमात्र नेता है और यह कि *महागठबंधन* से अलग होने और भाजपा से गठबंधन करने संबंधी

निर्णय श्री नीतीश कुमार द्वारा 26 जुलाई, 2017 को पटना में हुई बैठक में राज्य विधानमंडल दल के सर्वसम्मत अनुमोदन से लिया गया था। प्रतिवादी ने आगे बताया कि जद (यू) द्वारा लिए गए उक्त निर्णय का एकमात्र आधार राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जिसके नेता भ्रष्टाचार, धन शोधन और बेनामी संपत्ति के सौदों के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं, के साथ गठबंधन में रहकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना था। इस निर्णय को तत्पश्चात् 19 अगस्त, 2017 को पटना में हुई बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि वह याची ही था जिसने पार्टी के सर्वसम्मत निर्णय का पालन करने के बजाय, उसके विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू कर दिया और ऐसे कृत्यों से बाज आने के पार्टी द्वारा दी गई सलाह की अनदेखी की। उन्होंने बताया कि महागठबंधन केवल एक राजनीतिक गठबंधन था और उसमें शामिल होना या उससे अलग होना पार्टी के सर्वसम्मत निर्णय पर आधारित था और लोकतांत्रित दल परिस्थितियों में बदलाव के अनुसार और बहुमत की इच्छा को देखते हुए अपने पूर्व के निर्णयों से किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होते हैं। इसके अलावा, व्यक्तिगत राय सर्वसम्मत या बहुमत के निर्णय में सम्मिलित हो जानी चाहिए।

6. प्रतिवादी ने यह भी बताया कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में श्री नीतीश कुमार का निर्वाचन और अक्टूबर, 2016 में जद (यू) के भीतर संगठनात्मक निर्वाचन पूर्णतः पार्टी के संविधान और नियम के अनुसार हुए थे और उसके परिणाम नवम्बर, 2016 में भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को सूचित किए गए थे, जो सार्वजनिक अवलोकन के लिए ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि याची का इस आशय का तर्क कि जद (यू) के पिछले संगठनात्मक निर्वाचन 2013 में हुए थे, झूठा है और यह दलील दी है कि याची का यह दावा कि 2013 में संगठनात्मक निर्वाचन के बाद गठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद वास्तविक है, तथ्यों की दृष्टि से गलत है, क्योंकि अक्टूबर, 2016 के संगठनात्मक निर्वाचनों के परिणामस्वरूप नई राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी के गठित होने के बाद ये निकाय अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। उन्होंने यह दलील भी दी कि याची ने स्वयं 27 अप्रैल, 2016 को जद (यू) के भीतर संगठनात्मक निर्वाचन के संचालन के लिए कैलेण्डर जारी किए जाने को स्वीकार किया है, जिससे याची का समूचा मामला ही निरस्त हो जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी के आंतरिक चुनावों में विवाद के संबंध में याची और उनके दल द्वारा दायर की गई पूर्ववर्ती शिकायतों को ईसीआई द्वारा 7 फरवरी, 2017 को पहले ही यह समुक्ति करते हुए अस्वीकार कर दिया गया है कि इस मामले को पार्टी के संविधान में अपील संबंधी उपबंधों के अनुसार पार्टी के मंच के भीतर उठाया जा सकता है या निष्कासन आदि जो सिविल मामले हैं के संबंध में समुचित न्यायालय के समक्ष जाया जा सकता है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि आज की तारीख तक किसी निर्वाचन याचिका या सिविल मुकद्दमें में इसे कोई चुनौती नहीं दी गई है। जहां तक राज्य सभा में जद (यू) विधानमंडल दल के नेता के रूप में उनके निर्वाचन का संबंध है, उन्होंने यह पुष्टि की कि उन्हें संसद सदस्यों के बहुमत द्वारा चुना गया था।

7. संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) के अनुसार, किसी सदस्य को निम्नलिखित परिस्थितियों में निरहित किया जा सकता है:-

(क) यदि वह जिस राजनीतिक दल का सदस्य है, उसकी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता/देती है; या

(ख) स्य हैजब वह ऐसे राजनीतिक दल जिसका वह सद, द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विरुद्ध पूर्व अनुज्ञा के बिना सदन में मतदान करता/करती है या मतदान करने से विरत रहता/रहती है और ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और उठाये गए विवादों के संकीर्ण दिग्दर्शन को ध्यान में रखते हुए, मैं नियमावली के नियम 7 के उप-नियम (4) के अनुसार प्रतिवादी की निरर्हता के प्रश्न के अवधारण की कार्यवाई का प्रस्ताव करता हूँ। वस्तुतः, उत्तर पर विचार न करते हुए, याचिका की विषय-वस्तु के औपचारिक के बजाय सार्थक रूप से पठन से स्पष्टतः पता चलता है

कि याचिका में कोई दम नहीं है। अतः, याचिका को गहराई से पढ़ने और जाँच करने के बाद मुझे उत्तर का संदर्भ ग्रहण करने या उस पर विश्वास करने की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे भी मेरे समक्ष चल रही कार्यवाही किसी विचाराधीन वाद के समान नहीं है। डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद : (2004) 8 एससीसी 747 मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ सं. 16 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

"नियम 6 और 7 का उद्देश्य केवल इतना ही है कि वह आवश्यक तथ्य जिनके आधार पर सभा का कोई सदस्य पैराग्राफ 2 के अधीन सभा की सदस्यता से निरहता हो जाता है, सभापति के ध्यान में लाये जाएं। याचिका दायर करने वाले व्यक्ति और सभा के उस सदस्य जिसकी कथित रूप निरहता हुई है के बीच वाद विचाराधीन नहीं है। यह कोई विरोधात्मक प्रकार का मामला नहीं होता है जिसमें उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित हो। यदि वह अपनी याचिका वापस भी ले लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि संवैधानिक उपबंधों अर्थात् दसवीं अनुसूची के अधिदेश का पालन करने का दायित्व सभापति या लोकसभाध्यक्ष पर डाला गया है।"

इस प्रकार, उक्त निदेश को ध्यान में रखते हुए, मैं याचिका और उसके समर्थन में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री की अपनी जाँच, व्याख्या और विश्लेषण के आधार पर याचिका पर निर्णय का प्रस्ताव करता हूँ।

9. याचिका और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री को पढ़ने पर मैंने यह पाया है कि वर्तमान याचिका जद (यू) के अध्यक्ष के महागठबंधन से अलग होने और उसके बाद बिहार राज्य में सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने के निर्णय, जिसे 26 जुलाई, 2017 को हुई अपनी बैठक में राज्य विधानमंडल दल द्वारा और 19 अगस्त, 2017 को हुई बैठक में जद (यू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया था, के कारण प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता और अन्य के समूह ने यह दावा किया कि वे वास्तविक जद (यू) हैं और दूसरे समूह के कार्य पार्टी के सिद्धांतों और उसके संविधान और नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। अपने दावा को पुष्ट करने के लिए याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पार्टी के संविधान के अनुसार जद (यू) के भीतर समय पर संगठनात्मक चुनाव नहीं कराये गये और महागठबंधन से बाहर निकलने और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने संबंधी पार्टी अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार के निर्णय का विरोध करने की संभावना को दूर करने हेतु छलपूर्वक जद (यू) की राष्ट्रीय परिषद की शक्ति घटाने हेतु एक षडयंत्र किया गया।

10. उपर्युक्त कार्रवाई और आचरण के आधार पर याचिकाकर्ता ने अनुमान लगाया है कि प्रतिवादी ने स्वेच्छापूर्वक जद (यू) की सदस्यता छोड़ दी। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध एकमात्र कथित दल विरोधी गतिविधि उसके द्वारा नीतीश कुमार को सीधा समर्थन करना और उसका महागठबंधन से अलग होने और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का निर्णय है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ऐसी किसी गतिविधि को राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक छोड़ना माना जा सकता है जिसका वह सदस्य है।

11. इस संदर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 1 में 'विधान दल' और 'मूल राजनीतिक दल' की परिभाषा नीचे दी गई है, जो राजनीतिक दलों द्वारा किए गए किसी राजनीतिक गठबंधन का संज्ञान नहीं लेता है।

"व्याख्या 1. xxxx

(ख) *सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जो, पैरा 2 या [xxx] पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, "विधान-दल" से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं;*

(ग) *सदन के किसी सदस्य के संबंध में, "मूल राजनीतिक दल" से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है;"*

महागठबंधन बिहार में विधान सभा चुनाव लड़ने के प्रयोजनार्थ कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया राजनीतिक गठबंधन था और जनता दल (यूनाइटेड) इसके घटकों में से एक था। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा किसी राजनीतिक गठबंधन को छोड़ देना या उसमें शामिल होना किसी राजनीतिक दल में शामिल होने या उसे छोड़ देने जैसी बात नहीं है। इस प्रकार, किसी राजनीतिक गठबंधन को छोड़ देना या उसमें शामिल होना या उस प्रयोजनार्थ 'महागठबंधन' दल परिवर्तन-रोधी कानून के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

12. मैं यह भी समुक्ति करना चाहूंगा कि कोई राजनीतिक दल जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वह सामूहिक तौर पर लिए गए नियमों के आधार पर कार्य करता है और पार्टी में सामूहिक एवं सर्वसम्मति से लिए गये निर्णयों का पालन करने को किसी भी रूप में दलविरोधी गतिविधि नहीं माना जा सकता है और अतः प्रतिवादी के विरुद्ध याचिकाकर्ता का एकमात्र आरोप गलत है और इसमें कोई दम नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उपर्युक्त घटनाक्रम के अनुसरण में याचिकाकर्ता और कुछ अन्य व्यक्तियों ने अपने आप को श्री नीतीश कुमार के जद (यू) के धड़े से पृथक कर लिया है और उनके अनुसार जिस दल के प्रति उनकी निष्ठा है, वह श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी नहीं है। दूसरी ओर प्रतिवादी जद (यू) के उस धड़े के प्रति अपनी निष्ठा अभी भी रखता है जो जद (यू) का बहुमत वाला धड़ा माना जाता है।

13. याचिकाकर्ता का यह दावा कि जद (यू) का वह धड़ा जिसका वह हिस्सा है, वास्तविक जद (यू) है और श्री नीतीश कुमार और प्रतिवादी समेत उनके समर्थकों, जिन्होंने दल के संविधान और सिद्धांतों का उल्लंघन करके दल को छोड़ा है जिसके कारण वे अल्पमत वाले पृथक समूह बन गये हैं, वह 17 और 25 नवंबर, 2017 के भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के आलोक में भी मान्य नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले समूह को जनता दल (यूनाइटेड) के रूप में मान्यता दी है, क्योंकि उन्होंने विधान मंडल में प्रचुर बहुमत और राष्ट्रीय परिषद, जो इस दल का शीर्षस्थ संगठनात्मक निकाय है, में बहुमत का प्रदर्शन किया था।

14. इसी प्रकार याचिकाकर्ता का यह कथन कि प्रतिवादी को श्री शरद यादव को राज्य सभा में जद(यू) विधायक दल के नेता पद से स्वेच्छाचारी, मनमाने, मनमौजी तरीके से हटाकर उक्त पद पर अवैध तरीके से चुना गया, भी वहनीय नहीं है क्योंकि प्रतिवादी को 11 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में हुई जद (यू) संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से उक्त पद के लिए चुना गया था। लोक सभा सदस्य और संसद में जद (यू) के सदस्य श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा राज्य सभा सचिवालय को उपर्युक्त तथ्य की जानकारी दी गई थी और राज्य सभा सचिवालय द्वारा इसे संज्ञान में लिया गया था और तदनुसार राज्य सभा के अभिलेखों को अद्यतन कर दिया गया।

15. डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद एवं अन्य [(2004) 8 एससीसी 747] मामले में 27 अक्तूबर, 2004 को दिए गए निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित समुक्ति जो इस प्रसंग के अनुरूप है और निम्नानुसार उद्धृत है, से भी मैं उपर्युक्त निष्कर्ष तक पहुंचने में बंधा हुआ हूँ :-

"इसलिए, सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार सदन के सभापति या अध्यक्ष में निहित है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दसवीं अनुसूची सदन के सभापति या अध्यक्ष को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती है। उनकी भूमिका केवल संबंधित तथ्यों की जांच करने तक सीमित है। एकत्रित किए गए या प्रस्तुत किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाने पर कि सदन के किसी सदस्य ने ऐसा कोई कार्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 उप-पैरा (1), (2) या (3) के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसी स्थिति में निरर्हता लागू होगी और सदन के सभापति या अध्यक्ष को उस आशय का निर्णय लेना होगा।"

16. निष्कर्षतः याचिकाकर्ता ने मौजूदा मामले में यह साबित करने के लिए कोई तथ्य, प्रासंगिक या सामग्री, प्रस्तुत नहीं की है कि प्रतिवादी ने स्वेच्छापूर्वक अपनी गतिविधि या आचरण से जद (यू) की सदस्यता का भी परित्याग किया है। इस संबंध में दी गई सामग्री याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये निष्कर्ष को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं निर्णय देता हूँ कि प्रतिवादी श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह ने न तो अपनी किसी गतिविधि द्वारा और न ही अपने आचरण द्वारा जद (यू) की सदस्यता का स्वेच्छापूर्वक परित्याग किया है जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है और अतः याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया मामला किसी भी तरीके से संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1)(क) के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आता है।

17. अतः मेरा निर्णय है कि 30 अक्तूबर, 2017 को श्री अली अनवर अंसारी द्वारा दायर की गई याचिका में कोई दम नहीं है और यह कि प्रतिवादी श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (क) के अनुसार किसी प्रकार से अयोग्य नहीं है। न ही प्रस्तुत की गयी सामग्री की पृष्ठभूमि में इस प्रयोजन से किसी कल्पना को सामने रखकर उनके विरुद्ध ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उन्होंने उस राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छापूर्वक परित्याग किया है जिससे वह संबद्ध थे। तदनुसार याचिका रद्द की जाती है। मैं निर्णय देता हूँ और तदनुसार घोषणा करता हूँ।

नई दिल्ली

19 जनवरी, 2018

ह./-

(एम. वेंकैया नायडु)

सभापति, राज्य सभा

देश दीपक वर्मा, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23 January, 2018

No. RS.46/2017-T.—The following decision, dated the 19th of January, 2018, of the Chairman, Rajya Sabha, in the matter of petition of Shri Ali Anwar Ansari, Member, Rajya Sabha (since disqualified), in relation to Shri Ram Chandra Prasad Singh, another Member of the Rajya Sabha, given under paragraph 6(1) of the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:—

"ORDER

Shri Ali Anwar Ansari, Member (since disqualified) of the Janata Dal (United) [JD(U)] in Rajya Sabha (*hereinafter called 'the Petitioner'*), filed a petition before me on the 30th of October, 2017, under Article 102 (2) read with paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution of India and Rule 6 of the Members of the Rajya Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985 (*hereinafter called 'the Rules'*) praying that Shri Ram Chandra Prasad Singh, another Member and Leader of the JD(U) in the Rajya Sabha (*hereinafter called 'the Respondent'*), be disqualified under the Tenth Schedule to the Constitution and his seat be declared vacant in the Rajya Sabha.

2. The main allegation of the Petitioner is that the Respondent by openly pledging his support and allegiance to Shri Nitish Kumar and by supporting and actively participating in the alleged egregious activities of Shri Nitish Kumar, *namely*, (i) not conducting timely organizational elections within the JD(U) in accordance with the party constitution; (ii) devising a clever conspiracy to reduce the strength of the National Council of JD(U) in a fraudulent manner, so as to eliminate any chance of opposing him; and (iii) withdrawal from the *Mahagathbandhan* and formation of Government in Bihar with the support of the Bharatiya Janata Party (BJP), has betrayed the trust reposed by the people of Bihar through their mandate, all of which were for pure political and opportunistic reasons, had indicated his total disregard and lack of faith and allegiance to the party and its constitution. The Petitioner has alleged that these actions and conduct of the Respondent has *ipso facto* resulted in his voluntary abandonment of the party and its constitution and by necessary implication, which amounts to extinguishment of the membership of the party itself. He submits that the Respondent, who was elected to the Rajya Sabha on a JD(U) ticket, had been illegally appointed to the post of the Leader of JD(U) Legislature Party in Rajya Sabha by removing Shri Sharad Yadav from the said post in an arbitrary, whimsical and capricious manner, which is in complete breach of the party principles and its constitution. He further alleged that the Respondent by attending the meeting of the illegally constituted National Council on the 19th of August, 2017 and by supporting Shri Nitish Kumar in resiling from the *Mahagathbandhan*, which was approved by the then duly constituted National Executive on the 20th and 21st of December, 2015 as well as by the National Council on the 23rd of April, 2016, had indicated that he had decided to veer away from the basic tenets, principles and the binding resolutions of the Apex body of the JD(U) and that he does not have any faith or allegiance to the National Council or the National Executive and the party constitution.

3. The Petitioner has alleged that the Respondent has allied with Shri Nitish Kumar and his faction for sheer personal gain and political opportunism. He alleged that the autocratic and undemocratic manner of functioning of the Nitish Kumar faction has alienated the Nitish Kumar faction from the majority of the cadres and members of the organizational bodies of the JD(U) and have reduced them to a minority splinter group, which has broken ways with the

real JD(U) political party. The petitioner further submits that the mere fact that majority of the members of the JD(U) Legislature party, both at the State and in Parliament, have conducted themselves in similar fashion does not and ought not be used to validate their illegal actions and shield them from the disqualification that they have voluntarily incurred. In this regard, the Petitioner drew attention to the pending dispute before the Election Commission of India (ECI) wherein he along with Shri Sharad Yadav and their supporters had sought recognition of their faction as the real JD (U) and for allotment of the party symbol, Arrow, to them. In support of his allegations, the Petitioner has also annexed newspaper clippings, copies of the constitution of the JD(U); programmes and policies of the *Mahagathbandhan*; Resolution passed by the National Executive of JD(U) in its meeting held from the 20th to 21st of December, 2015; Resolution passed by the National Council in its meeting held on the 23rd of April, 2016; programme of the organisational elections within JD(U) in 2016; Resolution passed by the National Executive in its meeting held on the 17th of September, 2017; Resolution passed by the National Council in its meeting held on the 8th of October, 2017; the various representations/petitions filed before the ECI and the Orders passed by the ECI in this regard including the last application dated the 17th of October, 2017 and the affidavit dated the 22nd of August, 2017, filed by the Respondent before the ECI in support of the Nitish Kumar faction.

4. Having satisfied myself that the Petition complies with the requirements of Rule 6 of the Rules, I, in terms of sub-rule (3) of Rule 7, caused on the 10th of November, 2017, a copy of the Petition along with all Annexures thereto, to be forwarded to the Respondent, with the request to furnish his comments thereon, in writing within seven (7) days of the receipt of the same.

5. The Respondent furnished his comments on the 13th of November, 2017, wherein he submitted at the very outset that the Petition is misconceived and deserves no consideration, since it is not only based on incorrect facts, which have no basis or substance, but is also a lecture on standards of morality and ethics, which are neither relevant nor germane to an inquiry under the Tenth Schedule. The Respondent refuted the allegations made against him and termed them as false and factually incorrect by categorically asserting that there is no dispute about the leadership of the JD(U) and it is Shri Nitish Kumar, President of the JD(U), who alone heads the party and that the decisions regarding withdrawal from the *Mahagathbandhan* and aligning with the BJP were taken by Shri Nitish Kumar with the unanimous approval of the State Legislature party in the meeting held at Patna on the 26th of July, 2017. The Respondent further submitted that the sole basis of the said decision taken by the JD(U) was not to compromise on the issue of corruption by remaining aligned with the Rashtriya Janata Dal (RJD), whose leaders were embroiled in serious charges of corruption, money laundering and benami property dealings. This decision was subsequently approved unanimously by the National Executive and the National Council in a meeting held at Patna on the 19th of August, 2017. He also submitted that it was the Petitioner, who instead of adhering to the unanimous decision of the party, had started publicly speaking against the same and had chosen to ignore the advice given by the party to desist from such acts. He stated that *Mahagathbandhan* was only a political alliance and joining or breaking away therefrom was based on the unanimous decision of the party and democratic parties can in no way be bound to their past decisions in the face of change of circumstances and against the will of the majority. Moreover, individual opinions should get subsumed in unanimous or majority decisions.

6. The Respondent also submitted that the election of Shri Nitish Kumar as the Party President and conduct of organizational elections within the JD(U) in October, 2016 were held very much in accordance with the party constitution and rules and the results thereof had been intimated to the ECI in November, 2016, which is available on the ECI's website for public perusal. The Respondent alleged that the argument of the Petitioner to the effect that the last organizational elections within the JD(U) were held in 2013 was fallacious and contended that the claim of the Petitioner that the National Executive and National Council formed after the organizational elections in 2013 is the real one is factually incorrect, since these bodies cannot be in existence after the formation of new National Council and Executive consequent to the organizational elections of October, 2016. He further contended that the Petitioner himself has admitted to the issuance of the calendar on the 27th of April, 2016 for conduct of organizational elections within the JD(U), which has demolished the Petitioner's case in its entirety. He also clarified that the earlier complaints filed by the Petitioner and his faction regarding the dispute in internal party elections were rejected by the ECI on the 7th of February, 2017, with the observation that the same may be raised within the party forum as per the appeal provisions in the party constitution or appropriate Courts may be approached as regards expulsions etc., which are civil matters. He emphasized the fact that no challenge thereto has been brought forth in an election petition or civil suit, till date. As regards his election as the Leader of the JD(U) Legislature party in Rajya Sabha, he affirmed that he was elected by a majority of the MPs.

7. According to paragraph 2 (1) of the Tenth Schedule of the Constitution, a Member can be disqualified in the following circumstances:—

- (a) if he/she voluntarily gives up the membership of the political party to which he/she belongs; or
- (b) when he/she votes or abstains from voting in the House, contrary to any direction issued by the political party to which he/she belongs, without obtaining prior permission and such voting or

abstention has not been condoned by such party, within 15 days from the date of such voting or abstention.

8. Keeping in view the facts and circumstances of the case and narrow conspectus of the disputes raised, I propose to proceed with the determination of the question of disqualification of the Respondent, in terms of sub-rule (4) of Rule 7 of the Rules. In fact, irrespective of the reply, the contents of the petition, read meaningfully and not formally, clearly reveal that the petition is not possessed of any merits. Therefore, I need not even refer to or rely upon the reply, having read and examined the petition in depth. In any case the proceedings before me are not akin to a 'lis'. In *Dr. Mahachandra Prasad Singh Vs. Chairman, Bihar Legislative Council: (2004) 8 SCC 747*, the Hon'ble Supreme Court of India held in Paragraph No. 16 as follows:

"The purpose of Rules 6 and 7 is only this much that the necessary facts on account of which a member of the House becomes disqualified for being a member of the House under Paragraph 2, may be brought to the notice of the Chairman. There is no lis between the person moving the petition and the member of the House who is alleged to have incurred a disqualification. It is not an adversarial kind of litigation where he may be required to lead evidence. Even if he withdraws the petition it will make no difference as the duty is cast upon the Chairman or the Speaker to carry out the mandate of the constitutional provision viz. the Tenth Schedule."

As such, keeping in view the above dictum, I propose to decide the petition on the basis of my examination, interpretation and analysis of the petition and material filed by the petitioner in support thereof.

9. On perusal of the Petition and material available on record, I have found that the instant Petition has arisen due to the decision of the President of the JD(U), which was unanimously approved by the State Legislature Party in its meeting held on the 26th of July, 2017 and by the National Executive and the National Council of JD(U) in the meeting held on the 19th of August, 2017 to move away from the *Mahagathbandhan* and subsequently align with the BJP to form a Government in the State of Bihar. The group comprising the Petitioner and others claimed that they are the real JD(U) and the actions of the other group are a clear breach of the principles of the party and its constitution and rules. To buttress his contention, the Petitioner has alleged that organizational elections were not conducted timely within the JD(U) in accordance with the party constitution and a conspiracy was devised to reduce the strength of the National Council of the JD(U) in a fraudulent manner to eliminate chances of opposition to the Party President, Shri Nitish Kumar's decision to withdraw from the *Mahagathbandhan* and formation of Government in Bihar with BJP's support.

10. From the above actions and conduct, the Petitioner has inferred that the Respondent voluntarily gave up the membership of the JD(U). The only anti-party activity alleged against the Respondent by the Petitioner is his steadfast support of Shri Nitish Kumar and his decisions of withdrawing from the *Mahagathbandhan* and aligning with the BJP. The key question is as to whether such an activity can be construed as voluntarily giving up of his membership of the political party to which he belongs.

11. In this context, I would like to mention that the following definition of 'Legislature Party' and the 'Original Political Party' given in paragraph 1 of the Tenth Schedule to the Constitution, which does not take cognizance of any political alliance made by political parties:—

" Interpretation. 1. XXXXXXXX

(b) "legislature party", in relation to a member of a House belonging to any political party in accordance with the provisions of paragraph 2 or [xxx] paragraph 4, means the group consisting of all the members of that House for the time being belonging to that political party in accordance with the provisions;

(c) "original political party", in relation to a member of a House, means the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2."

The *Mahagathbandhan* was a political alliance of some political parties formed for the purpose of contesting the 2015 Legislative Assembly elections in Bihar and JD(U) was one of its constituents. As such, leaving or joining of any political alliance by political parties is not the same thing as joining or leaving a political party. Therefore, joining or leaving a political alliance or a '*gathbadhan*' or for that matter a '*mahagathbandhan*' would not fall within the purview of the anti-defection Law.

12. I would also like to observe that a political party, which is an essential part of the democratic set up, works through collective decisions and abiding by the collective and unanimous decisions of the party cannot in any manner be construed as an anti-party activity and therefore, the only allegation of the Petitioner against the Respondent is fallacious and lacks merit. Besides, it is as good as a conceded fact that the petitioner and some other persons, pursuant to the above

development, has disassociated themselves from the JD(U) of Shri Nitish Kumar faction and according to him, the party to which he owes his allegiance is not the party led by Shri Nitish Kumar. The Respondent on the other hand continues to hold allegiance to that faction of JD(U) which has been held to be the majority faction of JD(U).

13. The claim of the Petitioner that the faction of the JD(U) to which he belongs is the real JD(U) and it is Shri Nitish Kumar and his supporters including the Respondent, who had abandoned the party by breaching the party constitution and principles, due to which they have been reduced to a minority splinter group is also not tenable, in the light of the Orders of the ECI dated the 17th and 25th of November, 2017. The ECI in its Orders had recognized the group led by Shri Nitish Kumar as the Janata Dal (United), since they had demonstrated overwhelming majority support in the legislature wing as well as majority in the National Council, which is the Apex level organizational body of the party.

14. Similarly the submission of the Petitioner that the Respondent was illegally elected to the post of the Leader of the JD(U) Legislature Party in Rajya Sabha by removing Shri Sharad Yadav from the said post in an arbitrary, whimsical and capricious manner is also not sustainable, as the Respondent was unanimously elected to the said post, in the meeting of the JD(U) parliamentary party held in New Delhi, on the 11th of August, 2017. The above fact was intimated to the Rajya Sabha Secretariat by Shri Kaushalendra Kumar, Member, Lok Sabha and Leader of the JD(U) in Parliament and was taken cognizance of by the Rajya Sabha Secretariat and the records of the Rajya Sabha were updated accordingly.

15. In arriving at the above conclusion, I am also fortified by the following observation of the Hon'ble Supreme Court in its judgement, dated the 27th of October, 2004, in *Dr. Mahachandra Prasad Singh Vs. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors.* [(2004) 8 SCC 747], which is apposite in this context and is reproduced as under:—

" Therefore, the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraph (1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect."

16. To conclude, the petitioner in the instant case, has not furnished any fact, relevant or material, to establish that the Respondent has voluntarily given up the membership of the JD(U) by his action or conduct. Material produced is not sufficient to establish the inference made by the petitioner. Thus, after taking into account the facts and circumstances of the case, I hold that the Respondent, Shri Ram Chandra Prasad Singh, neither by his any action nor by his conduct has voluntarily given up the membership of the JD(U), as alleged by the Petitioner and therefore, the case agitated by the petitioner does not in any manner attract the provisions of paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution.

17. I, therefore, hold that the Petition filed by Shri Ali Anwar Ansari, on the 30th of October, 2017 has no merit and that, the Respondent, Shri Ram Chandra Prasad Singh, has not incurred any disqualification in terms of paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution. Nor, any such inference can be drawn against him by applying any deeming fiction to the effect, in the backdrop of the material produced that he voluntarily gave up the membership of the political party to which he belonged. Accordingly, the Petition stands dismissed. I decide and declare accordingly.

New Delhi,
January 19, 2018

Sd./-
M. VENKAIAH NAIDU
Chairman, Rajya Sabha"

DESH DEEPAK VERMA, Secy. General